TITLE CODE : UPHIN51496
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 222
दि. 13.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत... सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ

बाराबंकी (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान पाठशाला में खेती की चुनौतियों और उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21 फीसदी योगदान देता है। यह बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

सीएम योगी शुक्रवार को हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव में पद्मश्री और प्रगतिशील किसान रामसरन

वर्मा के फार्म पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम योजनाएं चलाई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ने बड़े स्तर पर किसानों को राहत दी है।

सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ-साथ यदि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियों, फल उत्पादन और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को अपनाने से सीमित भूमि पर भी शानदार उत्पादन संभव है। सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी प्रगति के बिना समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार हर जिले में किसान प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और आधुनिक मार्केट से जोड़ने की व्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खेती को लाभकारी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राष्ट्रपति ने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में निरंतर सहयोग करने का आग्रह किया

मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए गरिमा, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना और देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (12 दिसंबर, 2025) मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस अवसर पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के

आदिवासी समुदायों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में, मणिपुर के पहाड़ी जिलों को सड़क और पुल संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में किए गए लक्षित निवेशों से लाभ हुआ है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और वन धन जैसी आजीविका योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये प्रयास आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से 'कोलसेतु' विंडो को मंजूरी, पीएम मोदी बोले- इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिलेगी मदद

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने शुक्रवार को कोयला लिंकेज की नीलामी नीति में सुधार करते हुए निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग (कोलसेतु) के लिए नई विंडो को मंजूरी दे दी है। इस नई विंडो के माध्यम से किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का आवंटन किया जा सकेगा। इसे एनआरएस लिंकेज नीति में शामिल किया गया है। यह कदम कोयला क्षेत्र में सरकार के चल रहे सुधारों को और गति देगा।

कोयले के आसान, कुशल और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'कैबिनेट ने 'कोलसेतु' पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिससे कोयले के आसान, कुशल और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी, देश में कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और विकास को तेज करेगा।'

लिंकेज नीलामी नीति में 'कोलसेतु' नामक अलग विंडो

नई नीति 2016 की एनआरएस (नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर) लिंकेज नीलामी नीति में 'कोलसेतु' नामक अलग विंडो जोड़ती है, जिसके तहत नीलामी के माध्यम से दीर्घकालिक कोयला लिंकेज किसी भी घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता या निर्यात उद्देश्य के लिए आवंटित किया जा सकेगा।

एआई का विवेकपूर्ण इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा के लिए वरदान साबित हो सकता है: डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत में जैव प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी महत्वपूर्ण है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जीन थेरेपी और जैव प्रौद्योगिकी में

बढ़ते सार्वजनिक-निजी सहयोग पर प्रकाश डाला "भारत का फार्मा क्षेत्र निवारक स्वास्थ्य देखभाल के आयातक से वैश्विक निर्यातक में परिवर्तित हो रहा है" विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विवेकपूर्ण इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा और फार्मा क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी कमेटी का 20वां सत्र नई दिल्ली में सफलतापूर्वक खत्म हुआ

(जीएनएस)।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए वठएरउड की अंतर सरकारी कमेटी का 20वां सत्र आज नई दिल्ली के लाल किले में सफलतापूर्वक खत्म हुआ। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने अपने भाषण में इस प्रतिष्ठित वैश्विक बैठक की मेजबानी करने पर भारत की ओर से गहरी खुशी जाहिर की और जीवित विरासत की सुरक्षा, प्रचार और जश्न मनाने के लिए देश के लगातार प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों की बातचीत और विचार-विमर्श से प्रतिनिधियों को न केवल कन्वेंशन के काम करने के तरीकों से जुड़ने का मौका मिला, बल्कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, सबको साथ लेकर चलने और अलग-अलग तरह की परंपराओं का भी अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने संस्कृति को एक सामूहिक विरासत के रूप में देखने के भारत के लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत नजरिए पर जोर दिया, जो इस सिद्धांत से चलता है: 'संस्कृतिः रक्षणं, लोकस्य रक्षणम्' संस्कृति की रक्षा करके, हम मानवता की रक्षा करते हैं।

इस साल के सत्र की एक खास बात थी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की वठएरउड की प्रतिनिधि सूची में दीपावली का नाम शामिल होना। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत और उसके बाहर बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली दीपावली रोशनी, उम्मीद और नई जान डालने का प्रतीक है, और इसका नाम शामिल होना भारत की जीवंत परंपराओं की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। उन्होंने उन सभी सदस्य देशों को बधाई दी जिनके सिद्धांतों को इस सत्र के दौरान नाम शामिल करने की मंजूरी मिली।

सेशन के दौरान हुई चचाओं पर बात करते हुए, श्री अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समुदायों को बनाए रखने, सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने और परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्वीकरण, संघर्ष और जलवायु से जुड़े दबाव दुनिया भर के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डाल रहे हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि कई देशों ने बहुराष्ट्रीय अमूर्त विरासत नामांकन में ठोस दिलचस्पी दिखाई है, यह मानते हुए कि कई परंपराएँ स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं।

भारत ने इस मिलकर काम करने की भावना का स्वागत किया और आने वाले सालों में मिलकर अंतरराष्ट्रीय नामांकन का विकास करने के लिए अपनी तैयारी की पुष्टि की। श्री अग्रवाल ने वठएरउड के डायरेक्टर-जनरल डॉ. खालिद अल-एनानी, वठएरउड में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री विशाल वी. शर्मा, सेक्रेटरी सुश्री फुमिको ओहिनाता, सदस्य देशों, मान्यता प्राप्त ठग्र्ड्ढर, सांस्कृतिक व्यवसायी, और विशेषज्ञों का सत्र को असरदार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए भारत की तरफ से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान जैसे संगीत नाटक अकादमी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्ष्ण्ट्ठउअ, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की कोशिशों की भी तारीफ की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई।

अपना भाषण खत्म करते हुए, सचिव ने सभी सदस्य देशों से वैश्विक सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा देते रहने की अपील की, और अथर्ववेद का ज़िक्र किया: 'समानि वः वृणुते हृदयानि' हमारे दिल एकता का रास्ता चुनें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सत्र के दौरान रखे गए लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम सभा बैठक की अध्यक्षता की।

- श्री भूपेन्द्र यादव ने भारत के समुद्री उत्पत्ति स्थल के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर संस्थान के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की
- वैज्ञानिक काडर की क्षमता वृद्धि को मजबूत करें, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सामुदायिक भागीदारी के गहन एकीकरण के साथ विज्ञान-आधारित नीतिगत सहभागिता को बढ़ावा दें: सामान्य निकाय

(जीएनएस)।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की तीसरी आम सभा (जीबी) बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष के रूप में बैठक का नेतृत्व किया। विचार-विमर्श के इस सत्र में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और आम सभा के सदस्य भी सम्मिलित हुए। इस बैठक में तटीय और समुद्री अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों और जाने-माने वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया।

श्री यादव ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन, जलवायु अनुकूलन और समुद्री प्राकृतिक आवासों के पुनर्स्थापन के क्षेत्रों में एनसीएससीएम के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की। बैठक में एनसीएससीएम ने संरक्षण से लेकर आजीविका, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, द्वीपीय स्थिति, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, तटीय प्रक्रियाओं, समुद्र तटीय स्थानिक योजनाओं और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी।

आम सभा (जीबी) ने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने सहित कार्यक्रमों में वैज्ञानिक प्रयासों को सुदृढ़ करने और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और पारंपरिक ज्ञानवान लोगों के साथ सहयोगपूर्ण सहभागिता का विस्तार करने के निर्देश दिए। एनसीएससीएम को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि उसके अनुसंधान और क्षमता-निर्माण पहलों में विज्ञानझ्नीतिझ्समुदाय के एकीकरण को और गहरा किया जाए। जीबी ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीएससीएम के विजन दस्तावेज को विकसित भारत 2047 की थीम के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए।

जीबी ने तटवर्ती क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक काडर की क्षमता को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पदों पर नियुक्तियाँ और नई प्रतिभाओं को आगे लाना शामिल है। भर्ती नियमों से संबंधित एचआर नीति पर भी चर्चा की गई और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में वैज्ञानिक अधिगम और क्षेत्र-आधारित अनुसंधान में रुचि बढ़ाने के लिए इको-क्लबों, स्थानीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में संवेदनशील निर्णय

- वीसीई को राज्य सरकार के विभागों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 12 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन के आधार पर ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई) के तौर पर काम करने वाले युवाओं की अधिकतम आय सुनिश्चित करने वाला संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने इस संदर्भ में यह निर्णय किया है कि वीसीई को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के जरिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-सेवाओं जैसी ही सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराने के उद्देश्य से 'ई-ग्राम विश्वग्राम योजना' लागू की है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई), ग्राम स्तर पर लोगों को 7/12, 8-अ और अधिकार पत्र की प्रतिलिपि, किसान रजिस्ट्रेशन, विभिन्न खेत उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए फॉर्म भरने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वीसीई को विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री से संबंधित कार्य भी सौंपा जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग प्रत्येक कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट कमीशन के रूप में देय राशि निर्धारित करता है।

इसके कारण, अलग-अलग कामकाज और अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मेहनताने की राशि अलग-अलग आधार पर तय होने से मेहनताने में समानता नहीं रह पाती।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में जब यह विषय आया, तब उन्होंने हाल ही में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गांधीनगर में आयोजित 12वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसीई के मेहनताने में समानता के लिए तत्काल निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के चलते पंचायत विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित किया है कि अब किसी भी कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का मेहनताना देना होगा।

इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को वीसीई को कामकाज सौंपने से पहले पंचायत विभाग तथा ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को जानकारी भी देनी होगी।

रेल सुरक्षा रिकॉर्ड सुधार में वृद्धि : वार्षिक दुर्घटनाएं 2004-14 के औसत 171 से घटकर 2025-26 में अब तक 11 रह गई हैं

- सुरक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2013-14 के 39,463 करोड़ रूपए से चालू वित्त वर्ष में 1,16,470 करोड़ रूपए हो गया है
- अश्विनी वैष्णव ने कहा- कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 288 गुना बढ़ी है — 2014 के 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है
- पिछले चार महीनों में 21-21 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक-सर्किट का काम पूरा हो गया है

(जीएनएस)। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी असामान्य घटना की रेलवे प्रशासन द्वारा गहन जांच की जाती है। तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य कारण की आशंका होने पर राज्य पुलिस की सहायता ली जाती है।

कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से भी मार्गदर्शन लिया जाता है। हालांकि, जांच का प्राथमिक माध्यम राज्य पुलिस ही है। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पटरियों, पुलों, सुरंगों आदि रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्ष 2023 और 2024 में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़/तोड़फोड़ की सभी घटनाओं में, राज्यों की पुलिस/जीआरपी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया।

रेलवे द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी के साथ बेहतर समन्वय, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

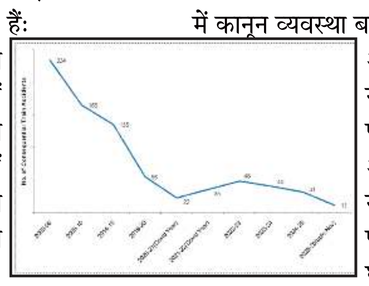

चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों और असुरक्षित इलाकों में रेलकर्मियों, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगातार गश्त की जा रही है।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, असुरक्षित इलाकों में गश्त करने और खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु विशेष दल गठित किए गए हैं।

रेलवे पटरियों के पास पड़ी सामग्री को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उपयोग शरारती तत्व रेलवे ट्रैक पर रखकर अवरोध उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं।

रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को ट्रैक पर अवांछित सामग्री रखने, रेल घटकों को हटाने के बाद होने वाली संभावित घटनाओं के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनसे सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया जा रहा है।

रेलवे राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनका गठन प्रत्येक राज्य में सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और खुफिया इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अपराध पर नियंत्रण, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसर के साथ-साथ चलती ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें तोड़फोड़ की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, स्थिति के अनुसार एनआईए और सीबीआई जैसी विशेष एजेंसियां भी शामिल हैं।

केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अलावा, आरपीएफ की खुफिया इकाइयां, यानी सीआईबी और एसआईबी को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है और उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे खुफिया जानकारी एकत्र करें और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से तोड़फोड़ के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुधारने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए अनुसार, परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है।

गौरतलब है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1711 थी (औसतन 171 प्रति वर्ष), जो 2024-25 में घटकर 31 और 2025-26 में (नवंबर 2025 तक) और भी घटकर 11 रह गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है:-

रेल संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं:-

भारतीय रेल में सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि हुई है:-

मानव विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 31.10.2025 तक 6,656 स्टेशनों पर बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं

लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 10,098 लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

विद्युत माध्यम से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 6,661 स्टेशनों पर पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है।

कवच एक अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है। इसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रारंभ में, कवच संस्करण 3.2 को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 आरकेएम और उत्तर मध्य रेलवे के 80 आरकेएम पर तैनात किया गया था।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण

- कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होगी
- वीजीआरसी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में संवाद-वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित
- रशिया, कनाडा और सिंगापुर सहित 20 से अधिक देशों के मिशन और दूतावास के प्रतिनिधि सहभागी हुए
- फिशरीज, पोर्ट, धोलेरा एसआईआर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर अर्थपूर्ण संवाद का प्लेटफॉर्म

गांधीनगर, 12 दिसंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से गुजरात वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है। इतना ही नहीं, गुजरात ने दुनिया भर के उद्योगों-निवेशकों के लिए 'गेट-वे टू द फ्यूचर' की विशेष पहचान स्थापित की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य विशेषताओं, क्षमताओं और आर्थिक विकास की संभावनाओं को उजागर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक

इस वीजीआरसी के राज्य में चार संस्करण आयोजित करने की योजना के अंतर्गत आगामी 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में सौराष्ट्रझ्र कच्छ क्षेत्र की वीजीआरसी का आयोजन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस संदर्भ में शुक्रवार, 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक चर्चा-संवाद सत्र का आयोजन किया। इस चर्चा-संवाद सत्र में, वीजीआरसी में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष वीजीआरसी की विशेषताओं की प्रस्तुति के साथ ही विकास संभावनाओं वाले सेक्टरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

इस संवाद सत्र में 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' थीम के अनुरूप और समावेशी, नवोन्मेषी एवं सतत-टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए गुजरात की विशेषताएं प्रस्तुत की गईं।

विशेषकर, फिशरीज, पोर्ट्स, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर सार्थक संवाद और बीटूबी (बिजनेस-टू-बिजनेस) की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा-परामर्श हुआ। साथ ही, वीजीआरसी में साझेदार देश बनने के फायदे, नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे विषयों पर भी वार्तालाप किया गया।

उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने चर्चा सत्र में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात क्षेत्र की पहली वीजीआरसी को मिली सफलता और 3.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जानकारी दी।

इस संवाद में रशिया, इजरायल, सिंगापुर, यूएई, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, आइसलैंड, गुयाना, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, कतर, तंजानिया, युगांडा और उज्बेकिस्तान सहित 20 से अधिक देशों के विदेशी मिशन और दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव, केंद्रीय मत्स्य पालन संयुक्त सचिव और इन्वेस्ट इंडिया की राज्य सुविधा टीम तथा गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, आर्थिक मामलों की सचिव श्रीमती आरती कंवर, सचिव श्री संदीप कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, पर्यटन सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ श्री राजकुमार बेनीवाल, रेजिडेंट कमिश्नर सह मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और धोलेरा एसआईआर के सीईओ श्री कुलदीप आर्य मौजूद रहे।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को संबोधित करेंगे

(जीएनएस)। संचार और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 13 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आयोजित होने वाले ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों के समर्पण और सेवा को सम्मानित करना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट की रीढ़ हैं। सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को जोड़ने तथा ग्रामीण भारत में डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं का विस्तार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना भी है।

डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महानिदेशक डाक सेवा श्री जितेंद्र गुप्ता, डाक सेवा बोर्ड के कार्मिक सदस्य श्री सुवेंदु कुमार स्वैन, महाराष्ट्र और गोवा सर्कल के मुख्य

डाक महानिरीक्षक श्री अमिताभ सिंह, डाक सेवा पुणे क्षेत्र के निदेशक श्री अभिजीत बंसोडे और डाक सेवा गोवा क्षेत्र के निदेशक श्री रमेश पाटिल भी उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम में गोवा और पुणे क्षेत्रों के विभिन्न मंडलों से 5500 से 6000 ग्रामीण डाक सेवकों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण डाक सेवा समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित डाक नेटवर्क के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे और उन्हें ग्रामीण समुदायों को सरकारी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिका को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे।

सम्मेलन के अंतर्गत, श्री सिंधिया डाक और पार्सल वितरण, नए डाक बचत खाते खोलने, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी खरीदने, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधे भुगतान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित करेंगे।

यह सम्मेलन ग्रामीण भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रवेश द्वार के रूप में इंडिया पोस्ट को सशक्त बनाने, प्रत्येक डाकघर को नागरिक-केंद्रित सेवाओं के केंद्र में बदलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

कुशल कार्यबल में वृद्धि और लघु उद्यमों की उत्पादकता में सुधार से भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि संभव: एनसीएईआर रिपोर्ट

श्रम-केंद्रित विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को दृढ़ करने से जीडीपी की 8 प्रतिशत वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिलेगी

ऋण सुविधा में 1 प्रतिशत की वृद्धि भी नियोजित श्रमिकों की अपेक्षित संख्या में 45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकती है

(जीएनएस)। नेशनल कॉंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल ने 11 दिसंबर, 2025 को "भारत में रोजगार की संभावनाएं: रोजगार के रास्ते" शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की। एनसीएईआर की प्रोफेसर फरजाना अफरीदी और उनकी शोधकर्ताओं की टीम द्वारा लिखित यह रिपोर्ट देश में रोजगार सृजन के प्रमुख कारकों के रूप में कौशल विकास और लघु उद्यमों की भूमिका पर बल देती है। एनसीएईआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यबल की गुणवत्ता और मात्रा तथा श्रम उत्पादकता बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वरोजगार में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है, जबकि कुशल श्रम बल की ओर बदलाव की प्रक्रिया धीमी रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रम प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने से जीडीपी की वृद्धि दर को लगभग 8 प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जो विकसित भारत के विजन के अनुरूप है।

एनसीएईआर के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है , और यद्यपि इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्तमान में 128वें स्थान पर है, यह रिपोर्ट रोजगार और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के बहुमूल्य अवसरों को रेखांकित करती है।"

प्रोफेसर अफरीदी ने कहा, 'भारत में स्वरोजगार की प्रधानता उद्यमशीलता की गतिशीलता के बजाय आर्थिक आवश्यकता के कारण है। छोटे किसानों की तरह, अधिकांश लघु उद्यम निर्वाह स्तर पर ही काम करते हैं। भारत को इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि उसका रोजगार भविष्य उसके सबसे छोटे उद्यमों की उत्पादकता से जुड़ा है।' मुख्य चुनौती यह है कि गैर-पंजीकृत घरेलू उद्यम पूंजी, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के निम्न स्तरों के साथ प्रचालन करते हैं।

उन्होंने कहा, 'डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले उद्यम, तकनीक का उपयोग न करने वाले उद्यमों की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। यहां तक कि ऋण सुविधा में 1 प्रतिशत की वृद्धि से भी नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि होती है।'

विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद रोजगार सृजन में बनी हुई चुनौतियों के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है आपूर्ति पक्ष पर, भारत के कार्यबल को कौशल विकास-विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकियों और एआई के आगमन से अत्यधिक लाभ हो सकता है। रोजगार वृद्धि में-खासकर सेवा क्षेत्र में-मध्यम-कुशल रोजगारों का दबदबा है जबकि विनिर्माण क्षेत्र निम्न कौशल-आधारित बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, "औपचारिक कौशल विकास में निवेश के माध्यम से कुशल कार्यबल की हिस्सेदारी में 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।"

अध्ययन में किए गए सिमुलेशन से पता चलता है कि मध्यम वृद्धि परिदृश्य के तहत औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल को बढ़ाने से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन हो सकता है। इसमें कहा गया है, "कुशल कार्यबल की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से 2030 तक 93 लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं।"

रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए, एनसीएईआर के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. जीसी मन्ना ने कहा कि यह रिपोर्ट रोजगार वृद्धि को गति देने की प्रबल क्षमता वाले प्रमुख सेक्टरों को रेखांकित करती है।

औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के विजिटिंग प्रोफेसर आदित्य भट्टाचार्य ने कहा, "यह रिपोर्ट भारत को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में रखती है और उन क्षेत्रों को उजागर करती है जहां देश के पास सुधार और वैश्विक मानकों के साथ मजबूत तालमेल बिठाने के अनूठे अवसर हैं।"

रिपोर्ट में अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के गुणक प्रभावों का आकलन करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि विनिर्माण और सेवाओं के भीतर अपेक्षाकृत अधिक श्रम-प्रधान उप-क्षेत्रों के सकल उत्पादन (जीओ) में मध्यम वृद्धि से 2030 तक कई गुना रोजगार सृजन होगा। विनिर्माण में वस्त्र, परिधान और संबंधित उद्योगों में 53 प्रतिशत और व्यापार, होटल और संबंधित सेवाओं में 79 प्रतिशत अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

यह रिपोर्ट विशिष्ट सेक्टरों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों की अनुशंसा करती है। विनिर्माण क्षेत्र में, उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों को वस्त्र, परिधान, जूते और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों की ओर पुनर्निर्देशित करने से रोजगार सृजन में वृद्धि हो सकती है। सेवा क्षेत्र में, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नीतिगत सहायता से व्यापक स्तर पर समावेशी रोजगार सृजित किया जा सकता है।

अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने बेहद भावुक क्षणों का अनुभव किया

प्रतिनिधिमंडल प्रार्थना करने के लिए हनुमानगढ़ी और सरयू नदी के तट पर गए

(जीएनएस)। काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों के चौथे बैच ने गुरुवार को एक बेहद भावुक और यादगार दिन बिताया। समूह ने हनुमानगढ़ी स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और पवित्र सरयू नदी के तट के दर्शन किए। इन अनुभवों ने प्रतिनिधिमंडल पर अमिट छाप छोड़ी।

भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन करते हुए प्रतिनिधिमंडल अत्यंत

भावुक हो गया। उन्होंने इस क्षण को आध्यात्मिक रूप से सार्थक बताया।

हनुमानगढ़ी में प्रतिनिधिमंडल ने भक्तिमय वातावरण में भगवान श्री हनुमान के मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस यात्रा ने उन्हें आंतरिक शक्ति का अनुभव कराया। उन्होंने बताया कि हनुमानजी की उपस्थिति ने उनमें नए सिरे से आत्मविश्वास जगाया।

दोपहर में प्रतिनिधिमंडल ने सरयू नदी के किनारे समय बिताया। उन्होंने पाया कि काशी तमिल संगम ने आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता के साथ सार्थक जुड़ाव प्रदान किया है, जिसमें श्री राम मंदिर के दर्शन विशेष रूप से यादगार रहे।

काशी तमिल संगमम 4.0 उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को निरंतर मजबूत कर रहा है। किसानों की यह यात्रा इस बढ़ते संबंध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

काशी तमिल संगमम 4.0 के 10वें दिन तमिलनाडु से काशी पहुँचा छठा दल

बनारस रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, छठे दल में महिलाएँ शामिल

(जीएनएस)। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम 4.0 में शामिल होने के लिए छठा दल काशी पहुँच गया है। इस दल में महिलाएँ शामिल हैं। जब यह दल विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया।

स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत देखकर तमिल दल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि काशी में मिल रहा आध्यात्मिक वातावरण उनके लिए अविस्मरणीय है। डमरू वादन की ध्वनि से पूरा परिसर शिवमय हो गया

और काशी व तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई दी।

कार्यक्रम के तय शेड्यूल के अनुसार, तमिलनाडु से आए ये डेलिगेट्स आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनझ्रपूजन करेंगे। इसके बाद वे गंगा तट, घाटों तथा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि अतिथियों को काशी की समृद्ध विरासत, कला, संस्कृति और अध्यात्म से परिचित कराने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

दल में शामिल लक्ष्मी काशी पहुँचने पर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, 'हमारा शुरू से सपना था कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। आज काशी पहुँचकर बहुत खुशी हो रही है।'

लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से काशी में आगमन होगा। वह अन्य महिलाओं के साथ दक्षिण भारतीय भाषा में भजन गाती हुई दिखाई दीं। उन्होंने कहा, 'हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे राज्य के लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। काशी और दक्षिण भारत का रिश्ता काफी पुराना है।'

पेशेवरों और कारीगरों के समूह की हनुमान घाट पर प्रार्थना

प्रतिनिधिमंडल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के निवास का दौरा किया और उनकी विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की

प(जीएनएस)। तमिलनाडु के पेशेवरों और कारीगरों से युक्त प्रतिनिधिमंडल का पांचवां बैच आज काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत हनुमान घाट पहुंचा। उन्होंने प्रार्थना की और समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रतिनिधिमंडल ने मां गंगा में स्नान करने के बाद घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने के साथ-साथ उनके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट स्थित महाकवि सुब्रमण्यम भारती के निवास स्थान का दौरा भी किया। उन्होंने निवास से जुड़े व्यक्तियों से बातचीत की और उनके जीवन और

योगदान के बारे में जानने में रुचि व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने पास के पुस्तकालय जाकर वहां के इतिहास और महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की।

महाकवि सुब्रमण्यम भारती को तमिल साहित्य और राष्ट्र आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तमिल के "राष्ट्र कवि" के रूप में पूजनीय महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने काशी में अपने प्रवास के दौरान संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया था।

महाकवि भारती के निवास स्थान का दर्शन करने के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने कांची मठ पहुंचकर उन्होंने वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल ने काशी के मध्य स्थित दक्षिण भारतीय मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल का मार्गदर्शन करने वाले वी चंद्रशेखर द्रविड़ घनपति ने बताया कि केदार घाट और हनुमान घाट के आसपास के इलाकों में पीढ़ियों से दक्षिण भारतीय परिवार बसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई परिवार पांच या दस पीढ़ियों से काशी में रह रहे हैं, स्थानीय परंपराओं को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को भी संरक्षित कर रहे हैं। इससे भगवान शिव की नगरी में उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

पेशेवरों और कारीगरों के इस प्रतिनिधिमंडल का काशी में निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है और बाद में नमो घाट का दौरा भी इसमें शामिल है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

विदेश मंत्री के बयान पर पाकिस्तान का जवाब

पाकिस्तान का जवाब पाकिस्तान ने अपनी सेना और इसके प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि सेना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जयशंकर का बयान भड़काऊ, बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना है। बता दें कि जयशंकर ने हिन्दुस्तान टाइम्स समिट के दौरान आसिम मुनीर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो इसके 80 साल पुराने इतिहास का प्रतिबिब है। जयशंकर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से सेना ही शासन करती है। कभी सेना खुलकर काम करती है, कभी पर्दे के पीछे से। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है और उसकी सभी संस्थाएं जिनमें सशस्त्र बल भी शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। यह संस्थाएं देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा मई 2025 के संघर्ष ने साफतौर पर पाकिस्तानी सेना की पेशेवर क्षमता और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संकल्प को साबित कर दिया है। कोई भी दुष्प्रचार अिंभयान इस सच्चाई को नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संस्थाओं और नेतृत्व को बदनाम करने की भारतीय नेतृत्व की कोशिश एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद क्षेत्र में भारत की अस्थिर करने वाली बयानबाजी शांति और स्थिरता के प्रति भारत की गंभीरता की कमी दशार्ती है। बता दें कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिस तरह अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी जैसी बातें की जाती हैं। उसी तरह अपने सैन्य नेता और उतने अच्छे सैन्य नेता नहीं होने की बात भी की जाती है। हिन्दुस्तान टाइम्स समिट में जयशंकर से यह भी पूछा गया था कि पाकिस्तान में नए चीफ ऑफ डिपेंस फोस्रेस के हाथ में जिस तरह सत्ता का बहुत ज्यादा वेंद्रीकरण देखा जा रहा है। उस पर आप क्या-क्या आंकलन है? आसिम मुनीर का इतनी गहराई से सत्ता में पंसे होने का भारत को फायदा है या नुकसान? जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तानी सेना हमेशा एक वास्तविकता की तरह रही है। अगर हम बात करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तो केवल हम ही नहीं उनके हाथ में भी इतनी शक्ति आने से संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। पाकिस्तान में हाल में हुए संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के उच्चायुक्त वोल्कर टर्व ने चेतावनी दी है कि 27वें संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। टर्व ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों को भी कमजोर कर सकता है, जिनसे देश में कानून-व्यवस्था बनी रहती है। बता दें कि पाकिस्तान में हालिया संवैधानिक बदलावों के बाद अब सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए हैं। उन्हें गत दिनों चीफ ऑफ डिपेंस फोस्रेस (सीडीएफ) बनाया गया है और इसी के साथ सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल नियंत्रण भी उनके हाथ आ गया है। नया तंत्र उन्हें वास्तविक परमाणु बटन का नियंत्रक बना रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार परमाणु हथियारों के नियंत्रण को इतनी स्पष्टता से सेना को सौंपा गया है कि इससे न केवल सैन्य प्रतिष्ठान की ताकत चरम पर पहुंच गई है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की राजनीति, सामरिक नीतियों और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों में सबसे निर्णायक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया है।

बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत 13 लाख से अधिक छात्रों को 370 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता वितरित की
- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की प्रेरक उपस्थिति
- नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सहायता वितरित
- राज्य सरकार ने अनेक शैक्षणिक योजनाएं कार्यरत कीं, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
- शिक्षा में किया गया निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

गांधीनगर, 12 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की उपस्थिति में नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के 13 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों को 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले ढाई दशक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी सफलतापूर्वक पूर्ण करें तथा कन्या शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ' अभियान के जरिए देश में बेटियों की शिक्षा को काफी बड़ी गति दी है। श्री पटेल ने कहा कि जब उन्होंने 2001 में गुजरात का सेवादायित्व संभाला, तब अनेक समस्याएं थीं। श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे समय में देश में एक उदाहरण पेश किया कि, किस प्रकार एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं गांव-गांव जाकर बेटियों की शिक्षा का सेवा-यज्ञ शुरू करता है।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें मिलने वाले उपहारों की नीलामी करके उससे प्राप्त होने वाली राशि को कन्या केळवणी (शिक्षा) के लिए देने की एक नई परंपरा शुरू की। इन सभी के परिणामस्वरूप लोगों में भी बेटियों को स्कूल भेजने की जागरूकता बढ़ी और शाला प्रवेशोत्सव-कन्या केळवणी महोत्सव की सफलता के चलते बेटियों के ड्रॉपआउट की दर 37 फीसदी से घटकर 2 फीसदी से भी नीचे आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गांवों में विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी जबकि आज विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या 2834 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2001 में केवल 775 कॉलेज थे, आज गुजरात में 3200 से अधिक कॉलेज छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 12 में विज्ञान संकाय के बाद इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए जाना हो, तो केवल 139 कॉलेज थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 288 पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला तब 1175 मेडिकल सीटें थीं, जो आज बढ़कर 7000 से अधिक हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल में पढ़ाई करने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना से अब तक राज्य की 24 हजार से अधिक बेटियों को सहायता प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात और देश का भविष्य जिनके हाथों में हैं, ऐसे आज के छात्रों के लिए गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं में से चार योजनाओं के अंतर्गत आज 13 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में सीधे 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता डीबीटी के जरिए भेजी गई है। अब तक, राज्य सरकार ने इन चारों योजनाओं के अंतर्गत कुल 13.50 लाख से अधिक छात्रों को 1332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है।

श्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को उनके दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और अपने स्वभाव के अनुसार सौम्यता के साथ पूरे मंत्रिमंडल की टीम को भी इसी प्रकार जनहित के निर्णय लेने के लिए लगातार प्रेरणा, छूट और हिम्मत दी है। शिक्षा विभाग की जिन चार योजनाओं के तहत आज छात्रवृत्ति सहायता दी गई है, उनमें से एक फ्लैगशिप योजना भी उनके ही निर्णय का हिस्सा है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिखाया है कि शिक्षा विभाग और हमारे भविष्य इन छात्रों के लिए उनका कितना समर्पण और योगदान है।

श्री संघवी ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में कहा कि गुजरात में जिस तरह से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे छात्र भी उसमें अपना योगदान दे सकें। यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे को विज्ञान संकाय में पढ़ाना चाहते हों, तो उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इन नेक विचारों के साथ राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका राज्य के अनेक छात्र लाभ उठा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने छात्रवृत्ति वितरण के अवसर पर कहा कि गुजरात सरकार विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग देश का भविष्य यानी आज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए योग्य दिशा देने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा में किया गया यह निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आने वाले समय के विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है। ये महत्वपूर्ण कदम गुजरात के छात्रों के जीवन को एक नई दिशा, नए अवसर और नए सपने देंगे।

गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली चार महत्वपूर्ण योजनाओं से आ रहे बदलावों की चर्चा करते हुए श्री वाजा ने कहा कि इन योजनाओं से लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो रहा है। नमो लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण का शक्तिशाली माध्यम बनी है। इस योजना के तहत अब तक 10.49 लाख बेटियों को डीबीटी के जरिए 1033 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके चलते बेटियों की उपस्थिति में 73 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में 13.59 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से विज्ञान संकाय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए 1.5 लाख छात्रों को 151.84 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे विज्ञान संकाय के नामांकन में 6.34 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेरिट और गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य दो योजनाएं- मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 50,000 छात्रों को 86.14 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत 60,000 छात्रों को 61.27 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों योजनाएं गुजरात के लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्ञानसेतु का निर्माण कर रही हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रत्येक बालक को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस विचार को साकार करने वाले आज के कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 13 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के जरिए 370 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

श्रीमती जाडेजा ने आगे कहा कि हमारे देश का प्रत्येक बालक उज्ज्वल भारत का स्वप्न है, इसलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती सहित अनेक योजनाओं के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर लगातार कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं में लगातार वृद्धि करना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य के छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सुंदर भविष्य बनाने का प्रयास करना है।

कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर शहर संगठन प्रमुख डॉ. आशीष दवे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मुकेश कुमार, निदेशक, स्कूल कार्यालय श्री प्रजेश राणा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

इशिता राज और सिद्धांत कपूर की 'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर रिलीज

'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर विभिन्न डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर दिया गया है, और इसे लेकर शुरूआती प्रतिक्रियाएँ भी आने लगी हैं। 2 मिनट और 8 सेकंड का यह ट्रेलर दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, जिसमें कई ऐसे दृश्य हैं जो गहन विचार-विमर्श के लिए मजबूर करते हैं। यह फि ल्म ड्रग रैकेट, अपराध और अस्तित्व की अनदेखी दुनिया की एक कच्ची और अशांत झलक देने का वादा करती है, जिसमें चौंकाने वाले और तीव्र पल भरे हुए हैं।

ट्रेलर में, पुष्कर जोग पूरी तरह से बदले हुए अंदाज में नजर आते हैं, एक ऐसे बंदी के रूप में जो एक खतरनाक और अटूट जाल में फँस चुका है। वहीं, इश्ता राज, जो अपने रोमांटिक किरदारों के लिए जानी जाती हैं, पहली बार एक डार्क, ग्रिटी और ग्रंज अवतार में दिखाई देती हैं। यह उनके एक्टिंग टैलेंट की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करता है। पुष्कर के साथ बंधक बनी इशिता अपने अभिनय में एक जमीनी और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे हर फ्रेम में तनाव और बढ़ जाता है।

सिद्धांत कपूर अपने अनोखे लुक के साथ एक खास प्रभाव छोड़ते हैं। ट्रेलर में वे काले मिनी ड्रेस में दिखते हैं, जो उनके रहस्यमयी और तेज-

तर्रार किरदार को और भी धार देता है। वरिष्ठ अभिनेता जाकिर हुसैन एक डरावने और शक्तिशाली किरदार में हैं, जो अपनी भयावह उपस्थिति से दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। यह सभी कलाकार फिल्म की गंभीरता को बढ़ाने में सहायक हैं।

'ह्यूमन कोकेन' एक नई, बेहद महंगी कोकीन वैरिएंट के उदय की कहानी बताती है, जिसे एक अत्यंत क्रूर और विचलित करने वाली प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। जैसे-जैसे यह डरावनी हकीकत सामने आती है, पुष्कर जोग और इशिता राज खुद को इसके अंधेरे और खतरनाक चक्रव्यूह में फँसा हुआ पाते हैं। यह फि ल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक दमदार कहानी पेश करती है, जो अंडरवर्ल्ड के उस अनदेखे हिस्से पर से पर्दा उठाती है।

फि ल्म के बारे में बात करते हुए, अभिनेता पुष्कर जोग ने बताया, "'ह्यूमन कोकेन' ने मुझे एक कलाकार और एक इंसान के तौर पर चुनौती दी। मेरा किरदार अपनी परिस्थितियों में फँसा हुआ है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह बेबसी, वह डर, वह गुस्सा-कैमरा बंद होने के बाद भी मेरे साथ बना रहा। यह मेरे करियर की सबसे तीव्र परियोजनाओं में से एक है।"

लेखक और निर्देशक सरिम मोमिन ने इस प्रोजेक्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "'ह्यूमन कोकेन' हमारे आसपास मौजूद एक डरावनी हकीकत का प्रतिबिंब है। इसे सहज या आसान देखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य है परेशान करना, सोचने पर मजबूर करना और बातचीत शुरू करना। इस फि ल्म का हर किरदार समाज के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम अक्सर छिपा देते हैं।"

इशिता राज, सिद्धांत कपूर, जाकिर हुसैन और ब्रिटिश कलाकारों की एक सशक्त टीम से सजी यह फि ल्म एक गहरा अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य रखती है। सरिम मोमिन द्वारा निर्देशित और लिखित इस फि ल्म को स्कारलेट स्लेट स्टूडियोज, वाइनलाइट लिमिटेड और टेक्स्टस्टेप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने गूजबम्प्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर निर्मित किया है।

डीएम का आदेश, शिक्षकों में हड़कंप! स्कूल के आठ किमी के दायरे में रहेंगे टीचर, जानिए क्यों

(जीएनएस)।

उत्तराखंड के टिहरी में डीएम के एक आदेश की प्रदेशभर में चर्चा हो रही है। टिहरी की जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने शिक्षकों के आठ किमी के दायरे में रहने संबंधी आदेश को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिसके बाद एक बार फिर ये आदेश चचाओं में आ गया है।

आदेश के मुताबिक, संबंधित विद्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षक निवास करेंगे। शिक्षक संगठन इस आदेश को लेकर पहले से ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि इस तरह का नियम पहले से ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग में है।

टिहरी के कीर्तिनगर में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया था और वहां फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पहुंच रहे थे। उसी बीच एक फरियादी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल उठाए और टीचरों की जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली। उन्होंने डीएम को बताया कि, 'सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों का ध्यान बेहद कम है।'

ज्यादातक टीचर दूरदराज इलाकों से वाहनों के जरिए स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में मात्र औपचारिकता पूरी करते है। फिर शाम को वापस लौट जाते हैं। उनकी मांग थी कि शिक्षक स्कूल के आसपास ही रहें ताकि वो विद्यालय और छात्रों पर ध्यान दे पाएं।

जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस बाबत औपचारिक आदेश जारी करने को कहा था।

आदेश के मुताबिक, संबंधित विद्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षक निवास करेंगे। टिहरी में इसी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षकों के विद्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहने के निर्देश दे दिए, जिस पर नईब बहस शुरू हो गई है। जिलाधिकारी का ये आदेश काफी चचाओं में आ गया है। शिक्षक संगठन पहले ही इस तरह के आदेश को अव्यवहारिक बता चुके हैं। जिसके बाद एक बार फिर शिक्षक संगठन और विभाग में खींचतान होनी तय है।

सेमीकंडक्टर के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम एक संपूर्ण व्यवस्था विकसित कर रहा है

- उत्पादन और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहनों के अलावा, सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं के विकास पर भी काम कर रही है

(जीएनएस)।

सेमीकंडक्टर विकास रणनीति, माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन से प्रेरित है।

अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की मूलभूत प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग सहित एक संपूर्ण व्यस्था तैयार करने के लिए 'सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया।

सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, 1.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश से दस (10) इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सिलिकॉन फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, उन्नत पैकेजिंग, मेमोरी पैकेजिंग आदि शामिल हैं।

ये इकाइयां उपभोक्ता उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, एयरोस्पेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों की चिप की जरुरतों को पूरा करेंगी।

मंजूर प्रस्तावों में से कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार ने मोबाइल फोन और कुछ विशिष्ट घटकों के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की है। इस योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 14,065 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।

आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को लक्षित करते हुए, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई

शुरू की।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के तहत अक्टूबर 2025 तक 846 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।

इन नीतिगत प्रयासों के नतीजतन, पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण करीब 6 गुना बढ़ गया है। यह 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़कर 2014-15 में 38 हजार करोड़ रुपये से 2024-25 में 3.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अब निर्यात की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी है।

डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना

चिप डिजाइन में भारत की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना की शुरुआत की।

उपग्रह संचार, ड्रोन, निगरानी कैमरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण, एलईडी ड्राइवर, एआई उपकरण, दूरसंचार उपकरण, स्मार्ट मीटर आदि उत्पादों के लिए चिप्स और एसओसी डिजाइन करने के लिए 23 कंपनियों (24 डिजाइनों) को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, ढ़ांचागत सहायता के रूप में, 94 स्टार्टअप्स को निशुल्क डिजाइन टूल (ईडीए) की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे 47 लाख घंटे का डिजाइन टूल उपयोग संभव हुआ है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं का विकास

सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं का विकास करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है:

चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम: भारत के युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार 397 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को नवीनतम डिजाइन टूल (ईडीए) उपलब्ध करा रही है।

इन टूल का इस्तेमाल करके, 46 से अधिक विश्वविद्यालयों के चिप डिजाइनरों ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) में 56 चिप्स डिजाइन और निर्मित किए हैं।

चिप डिजाइन में अब तक 67,000 से अधिक छात्रों और शोधकताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन) में बी.टेक,

इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) निर्माण में डिप्लोमा, और

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी) में माइनर डिग्री

1 लाख इंजीनियरों को राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण देने के मकसद से एनआईईएलआईटी कालीकट में एक कुशल मानव संसाधन उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण (स्मार्ट) प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अब तक 62 हजार से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

आईएसएम ने नैनोफैब्रिकेशन और प्रोसेस-इंजीनियरिंग कौशल में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लैम रिसर्च के साथ साझेदारी की है। इससे एटीएमपी और उन्नत पैकेजिंग के लिए कुशल कार्यबल में और वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 60,000 प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम भारत को अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभाओं का देश बनाने के मकसद से एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक संयुक्त पहल है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और उन्नत कौशल विकास।

रोजगार की असल जरुरतों के मुताबिक उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजना: पीलीभीत में कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण के लिए चिन्हांकन शिविर

(जीएनएस)।

पीलीभीत,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पीलीभीत जिले में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली योजना के तहत चिन्हांकन शिविर आयोजित हो रहे हैं। ये शिविर विभिन्न विकास खंडों और नगर पालिकाओं में निर्धारित तिथियों पर लगेंगे, जहां दिव्यांगजन अपना पंजीकरण करा सकेंगे। प्रत्येक शिविर सुबह 10 बजे से शाम तक चलेगा, और इसमें योग्य लाभार्थियों की जांच व चिन्हांकन किया जाएगा। यह पहल दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, जो सरकारी योजना का हिस्सा है।

शिविरों का विस्तृत विवरण

नीचे दिए गए क्रमांक के अनुसार शिविरों की सूची है:

क्र.सं.शिविर स्थल शिविर की तिथि,समय

विकास खण्ड पूरनपुर 16.12.2025-10 बजे से कार्य समाप्ति तक

नगर पालिका पूरनपुर 17.12.2025-10 बजे से कार्य समाप्ति तक

विकास खण्ड - मरौरी व पीलीभीत सदर क्षेत्र 18.12.2025-10 बजे से कार्य समाप्ति तक

नगर पंचायत - न्यूरिया हुसैनपुर 19.12.2025-10 बजे से कार्य समाप्ति तक

अधिकारी हस्ताक्षर:

(सुरेश कुमार मौर्य) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पीलीभीत।

(राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव) मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

(ज्ञानेन्द्र सिंह) जिलाधिकारी, पीलीभीत।

नगर पालिका विकास खण्ड में दिव्यांगजनों के कैम्प आयोजित होंगे,पूरनपुर पीलीभीत दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजनान्तर्गत जनपद पीलीभीत विकास खण्डों में आयोजित किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुये अटल भारतीय हिन्दू फाउन्डेशन के जिलाध्यक्ष अजय प्रकाश पांडे ने बताया कि विकास खण्ड पूरनपुर में 16 दिसम्बर को विकास खण्ड परिसर एवं 17 दिसम्बर को नगर पालिका कार्यालय में आयोजित होगें एवं विकास खण्ड मरौरी व पीलीभीत सदर में 18 दिसम्बर न्यूरिया हुसैनपुर में 19 दिसम्बर को आयोजित किये जायेगें,

सभी दिव्यांगजन अपने जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे जैसे कि आधार कार्ड विकलांग सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र आदि, जिलाध्यक्ष श्री अजय प्रकाश पांडे ने सभी विकलांगजनों को मूल प्रमाण पत्रों सहित पहुंचकर कैम्प में लाभ उठाने की अपील की गई।

जोगराजपुर स्टेशन चौराहा पर खराब हेड पंप से राहगीर परेशान, ग्राम प्रधान व प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

(जीएनएस)।

पीलीभीत,12 दिसंबर: जोगराजपुर के स्टेशन चौराहा स्थित मार्केट में लगे हेड पंप के खराब होने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह पंप लंबे समय से ठप है, लेकिन मरम्मत की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोजाना हजारों लोग इस व्यस्त मार्केट से गुजरते हैं, फिर भी बुनियादी सुविधा की कमी से सभी परेशान हैं।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और संबंधित सरकारी कर्मचारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। एक निवासी ने बताया, "राहगीरों को पानी पीने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है, जबकि यह सरकारी सुविधा है।" उनका कहना है कि सरकारी नीतियों के तहत स्थानीय प्रशासन व ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और खराबी की तुरंत मरम्मत हो।

इस लापरवाही से सवाल उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन व ग्राम प्रधान क्या कदम उठाते हैं। क्या हेड पंप की शीघ्र मरम्मत होकर राहगीरों को राहत मिलेगी, या मुद्दा अनदेखा रह जाएगा?

बीएलओ त्रिवेणी सिंह को एसआईआर कार्य समय से पूर्ण करने पर मिला सम्मान

1106 निर्वाचकों का डिजिटाइजेशन; सुपरवाइजर ने फूलमाला पहनाकर सराहा

(जीएनएस)।

पूरनपुर, पीलीभीत।

पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जहूरगंज में बीएलओ त्रिवेणी सिंह को एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) कार्य समय से पूर्व पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने 1106 निर्वाचकों की जानकारी का डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा से पहले सफलतापूर्वक किया।जिस पर उन्हें शुक्रवार को विद्यालय में सुपरवाइजर सौरभसाख्यधर ने त्रिवेणी सिंह को फूलमाला पहनाकर उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की और बधाई दी।निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी बीएलओ को मतदाता सूची के संशोधन, सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य निर्धारित समय में पूरा करना था। त्रिवेणी सिंह ने इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त किया।कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने त्रिवेणी सिंह के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि समयबद्धता, सतर्कता और तकनीकी दक्षता बीएलओ के कार्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। त्रिवेणी सिंह द्वारा लक्ष्य को समय से पहले पूरा करना अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक है और इससे मतदाता सूची सुधार कार्य को गति मिली है।सुपरवाइजर सौरभ साख्यधर ने इस अवसर पर कहा कि कर्मठ और ईमानदार बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सभी कर्मचारी इसी प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।इस कार्यक्रम में स्थानीय शिक्षक और कई अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने बीएलओ त्रिवेणी सिंह के प्रयासों की सराहना की।

महिलाएं हुनरमंद बनेंगी तभी देश का संपूर्ण विकास होगा संदीप कुमार श्रीवास्तव

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। महिलाएं हुनरमंद बनेंगी तभी देश का संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त और कुशल महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं और नई दिशा देती हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक प्रगति होती है.।

उक्त बाते पंचायत भवन बड़ागांव मे आज से शुरू हुए 15 दिवसीय जरी जरदोजी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करते हुए खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कही उन्होंने कहा कि जरी जरदोजी प्रशिक्षण का शुभारम्भ अब केवल एक कला सीखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन गया है, जिसमें सरकार और स्वयंसेवी संगठन मिलकर कारीगरों, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र डालीगंज लखनऊ की प्राचार्य श्रीमती तनुजा ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले में जरी-जरदोजी के तहत स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो एक महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) का संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जिले में जरी-जरदोजी का चयन किया गया है। ऐसे में जिले में जरी-जरदोजी के काम को आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार महिलाओ को प्रशिक्षित कर योजना से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है । राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बड़ागांव के प्रधानाचार्य महेश चंद्र ने कहा कि शिक्षित और कुशल महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर निर्णय लेती हैं, जिससे पूरे समाज की प्रगति होती है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह प्रशिक्षण मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को पारंपरिक हुनर जैसे बुनाई, कढ़ाई और वस्त्र निर्माण में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है।

इस मौके पर खण्ड विकास अधिकारी रामनगर जितेंद्र कुमार ,ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद,

प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह जितेंद्र नाथ शुक्ला प्रशिक्षक महशर जहां, पंचायत सहायक सैय्यदा बानो सहित प्रशिक्षार्थी महिलाए मौजूद रही।

माघ मेला 2025-26 के लिए साधु-संतों व संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रस्तावित तिथियां

(जीएनएस)।

अपर मेलाधिकारी, माघ मेला ने बताया है कि माघ मेला 2025-26 में साधु-संतो, संस्थाओं एवं प्रयागवाल/तीर्थपुरोहितों को विगत वर्षों की भांति परम्परानुसार भूमि/सुविधाओं का आवंटन किया जाना है। माघ मेला 2025-26 में दिनांक 15.12.2025 को अरैल, नागवासुकी मार्ग, हरिशचन्द्र मार्ग के लिए भूमि का आवंटन, प्रयागवाल/तीर्थपुरोहित के लिए भूमि आवंटन 16 दिसम्बर से प्रारम्भ, 16 दिसम्बर को गंगोली शिवाला मार्ग, ओल्ड जी0टी0 मार्ग, अलोपशंकरी मार्ग एवं तुलसी मार्ग, दिनांक 17 दिसम्बर को समयामाई मार्ग, सूरदास मार्ग, गणपति मार्ग, कबीर नगर 18 दिसम्बर को अक्षयवट मार्ग, संगम वापसी मार्ग, लाल सड़क, परेड, हर्षवर्धन मार्ग, अन्नपूर्णा रामानुज मार्ग, 19 दिसम्बर को त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग, संगम अपर मार्ग, सरस्वती मार्ग, महावीर मार्ग, मोरी मार्ग, गाटा मार्ग एवं अन्य संस्थाए एवं 20 दिसम्बर को समुद्रकूप मार्ग एवं इण्टरलॉकिंग मार्ग से0-4, भारद्वाज मार्ग, संगम लोवर मार्ग एवं शास्त्री गाटा के लिए भूमि का आवंटन किया जायेगा।

अपर मेलाधिकारी, माघ मेला ने बताया है कि सुविधा पर्चियों की प्राप्ति हेतु पहचानयुक्त फोटो एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन सम्भव है। कहा है कि जिन संस्थाओं द्वारा विगत वर्ष कुम्भ/महाकुम्भ/माघ मेला अथवा अन्य किसी वर्षों में टिन, टेण्टेज, फर्नीचर की सुविधायें प्राप्त कर वापस नहीं की गयी है, उन्हें वर्तमान वर्ष में किसी भी प्रकार की भूमि एवं सुविधा देय नहीं होगी। प्रत्येक शिविर धारक को मेले की सम्पूर्ण अवधि (माघी पूर्णिमा) तक शिविर बनाये रखना अनिवार्य होगा। सुविधा पर्ची, भूमि आवंटन के 02 दिन के पश्चात निर्गत की जायेगी।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। पीलीभीत

बीसलपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने ग्राम रिछौला सबल, थाना बीसलपुर में कैफ रजा (कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सदस्यता अभियान चलाया गया।

कैफ रजा ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों व वंचितों के हक-अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने बताया कि राजभर स्वयं धरातल पर कार्यरत रहते हैं, जिससे पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। कैफ रजा ने कार्यकताओं को संबोधित कर कहा, "हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने दम पर, अपने सिंबल पर लड़ेगी। कार्यकताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पूरे प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेंगे।" उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारी करने और धरातल पर काम करने का आ'ान किया।

कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अहमद जिया (पिछड़ा वर्ग), वेद प्रकाश, गालिब हुसैन, इकबाल हुसैन, अवधेश यादव, रशीद अंसारी, अनवर हुसैन, अकरम अंसारी, राजू वर्मा, जुल्फिकार हुसैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने सदस्यता अभियान को तेज करने का संकल्प लिया।

किर्गिस्तान में फंसे 13 युवाओं की सुरक्षित वापसी का आश्वासन- केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने परिवारों से दिल्ली में मुलाकात की

(जीएनएस)।

पीलीभीत। केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद जितिन प्रसाद पीलीभीत के विकास के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में, बरखेड़ा, गजरौला व पूरनपुर के 13 परिवारों के युवाओं के किर्गिस्तान में फंसने की सूचना मिलने पर उन्होंने परिवारजनों को दिल्ली बुलाकर मुलाकात की। जितिन प्रसाद ने युवाओं की सुरक्षित वापसी का आश्वासन दिया।

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में जितिन प्रसाद ने लिखा, "पीलीभीत के 13 परिवारों के युवाओं के किर्गिस्तान में फंसे होने की जानकारी पर परिवारों को नई दिल्ली बुलाकर विषय की जानकारी ली। युवाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्राथमिकता हर भारतीय की सुरक्षा है। इस संबंध में विदेश राज्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, और जल्द ही सभी की सुरक्षित वापसी हो जाएगी।

जिसमें वहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह व किसान नेता देव स्वरूप पटेल आयुष मिश्रा मनोज गुप्ता लेखराज भारती सहित कई प्रतिनिधि परिजनों के साथ मौजूद रहे

परिवारजन जितिन प्रसाद के इस कदम से आशान्वित हैं। जिले के विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा पर भी उनका ध्यान है।

धरती का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी बची रहेगी सृष्टि: योगी आदित्यनाथ

प्रगतिशील किसान सम्मेलन में खेत पर गूंजी खेती की बात, रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि बची रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल विजन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है ये उसी कड़ी का हिस्सा है। वे हमेशा कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो तथा उत्पादन ज्यादा हो। अन्नदाता किसान को समय पर बीज, खाद, सिंचाई की सुविधाएं तथा वैज्ञानिक पद्धतियों का सहयोग मिले तो ये संभव है। शुक्रवार को बाराबंकी के दौलतपुर ग्राम में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन तथा खेती की बात खेत पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ किया। खेत पर पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश की कृषि प्रगति, बहु फसली खेती, तकनीकी नवाचार, एमएसपी व्यवस्था की पारदर्शिता और किसानों की आय वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को चेक व स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रदर्शनी में उन्नत किस्मों की फसलों, सब्जियों, कृषि यंत्रों और एफपीओ आधारित नवाचारों का अवलोकन भी किया गया, जबकि दौलतपुर की उन्नत खेती के मॉडल को प्रदेश के अन्य जनपदों के लिए प्रेरणा बताया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, जहां 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों में प्रदेश ने समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उर्वरक भूमि, पर्याप्त जल संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण राज्य कृषि और अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी बना है। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 11 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति में प्रदेश का योगदान 21 प्रतिशत है। सरकार ने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी सुनिश्चित की है। स्वॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा, गन्ना भुगतान, कृषि मंडियों के विस्तार तथा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को मिल रहा है जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में हर खेत को पानी उपलब्ध कराने, माइक्रो इरीगेशन, नहरों के नेटवर्क, सौर पंप और जल संरक्षण के अभियानों को गति दी गई है। ड्रोन डोजिंग, खरपतवार नियंत्रण, स्वॉइल टेस्टिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मंडी और ई नाम जैसे प्रयासों ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स पार्कों के माध्यम से किसानों की उपज अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से पहुंच रही है। विश्व बैंक के सहयोग से 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से छह वर्षों में यूपी-एग्रीज परियोजना के अंतर्गत कम उत्पादन वाले 28 जनपदों, विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड, में कृषि सुधारों को गति दी गई है मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौ भौगोलिक जलवायु क्षेत्र हैं और इनके अनुरूप उन्नत बीज तथा तकनीक उपलब्ध कराने पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले की तुलना में आज रिकॉर्ड उत्पादन और पारदर्शी व्यवस्था ने प्रदेश की प्रगति को नई दिशा दी है। कृषि विकास दर को 8.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.7 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, एक एकड़ में ढाई सौ क्विंटल आलू और दो लाख रुपये मूल्य का केला उत्पादन लागत कम और उत्पादन अधिक का सफल उदाहरण है। एफपीओ के माध्यम से सहकारी खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

मलिहाबाद में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ भगवत कथा शुरू

(जीएनएस)।

मलिहाबाद। धर्म और आस्था का संगम लिए गौशाला में सात दिवसीय भागवत कथा और सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शुक्रवार से शुरू हुआ। इस पुनीत आयोजन की शुरूआत आज सैकड़ों भक्तों द्वारा एक भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा के साथ की गई, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया।मंगल कलश शोभा यात्रा गौशाला से प्रारंभ हुई और परम शिवालय, बुढ़िया शिवालय सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख मंदिरों से गुजरी। यात्रा में शामिल सैकड़ों महिलाओं व कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा का नेतृत्व किया। रास्ते में भक्तों और मंदिर समितियों ने कलश यात्रा का जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गोपूजन के साथ ही गोपेश्वर महादेव की विशेष आराधना भी की गई, जिसमें क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित जन उपस्थित रहे।

कलश यात्रा के सफल समापन के बाद शुक्रवार से सात दिवसीय संगीतमय कथा का वाचन प्रारंभ होगा। यह कथा आचार्य स्वामी माधव शरण महाराज के मुखारबिन्दु से भक्त श्रवण करेंगे।धार्मिक अनुष्ठान का समापन 18 दिसंबर को किया जाएगा। कथा के दौरान राम राज्याभिषेक जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा जिसका लाभ क्षेत्र के श्रद्धालु उठा सकेंगे।

मलिहाबाद में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ भगवत कथा शुरू

तेज प्रताप यादव ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, अब इन 2 राज्यों में चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी JJD

(जीएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ साझा कीं। उन्होंने घोषणा की कि JJD अब क्षेत्रीय दायरा तोड़कर 2025 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी।

उनका लक्ष्य JJD को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना और पूरे देश में सदस्य बनाना है। पटना में स्वयं सदस्यता ग्रहण करते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा, उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रभावितों के लिए व्यवस्था और अपनी बहन रोहिणी आचार्य को सुरक्षा देने की मांग भी उठाई।

JJD का राष्ट्रीय विस्तार: बंगाल से यूपी तक

तेज प्रताप यादव ने JJD को एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। इसकी शुरूआत 2025 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा से हुई है। उनका मानना है कि चुनाव के बाद जहाँ अन्य पार्टियां शिथिल पड़ जाती हैं, वहीं JJD पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार सदस्यता अभियान चलाकर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। उनका तत्काल लक्ष्य पूरे देश में सदस्य बनाकर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिलाना है, जिसके लिए पार्टी की वेबसाइट भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी।